गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 269
दि. 31.01.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

कांग्रेस में पिघली जमी बर्फ, थरूर के बदले सुरों से निकला एकजुटता का संदेश

(जीएनएस)। नई दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में गुरुवार और शुक्रवार को कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को लेकर अचानक हलचल तेज हो गई। लंबे समय से जिस बात की चर्चा थी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और पार्टी नेतृत्व के बीच रिश्तों में ठंडापन आ गया है, उसी 'बर्फ' के पिघलने के संकेत अब साफ दिखाई देने लगे हैं। गुरुवार को राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ थरूर की करीब दो घंटे चली बैठक के बाद जो तस्वीर उभरकर सामने आई, उसने पार्टी के भीतर चल रही तमाम अटकलों पर काफी हद तक विराम लगा दिया।

इस बैठक के ठीक अगले दिन शुक्रवार को शशि थरूर ने जिस तरह से राहुल गांधी की सार्वजनिक रूप से सराहना की, उसने राजनीतिक हलकों में इसे एक बड़े 'पॉलिटिकल यू-टर्न' के रूप में देखा जाने लगा। थरूर ने राहुल गांधी को न केवल ईमानदार नेता बताया, बल्कि उन्हें देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ एक "सशक्त और मुखर आवाज" करार दिया। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब बीते महीनों में थरूर के कुछ रुख और टिप्पणियां कांग्रेस के आधिकारिक स्टैंड से अलग नजर आ रही थीं और उन्हें लेकर पार्टी के भीतर असहजता भी महसूस की जा रही थी।

दरअसल, पिछले कुछ समय से खासकर केरल कांग्रेस में शशि थरूर की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। यह चर्चा आम थी कि पार्टी नेतृत्व उन्हें दरकिनार कर रहा है और थरूर इससे नाराज हैं। कुछ मौकों पर उनके बयान ऐसे समझे गए, मानो वे केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना कर रहे हों। इसी वजह से राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया के एक हिस्से ने यह तक कहना शुरू कर दिया था कि थरूर कांग्रेस नेतृत्व से दूरी बना रहे हैं या फिर भविष्य में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ हुई इस हालिया बैठक ने इन तमाम कयासों को कमजोर कर दिया है।

बैठक के बाद थरूर ने साफ कहा कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है और कांग्रेस पूरी तरह एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने "हम साथ-साथ हैं" का संदेश देते हुए यह जताने की कोशिश की कि मतभेदों की जो बातें सामने आ रही थीं, वे अब

अतीत की बात हैं। थरूर के बदले हुए सुर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व और उनके बीच संवाद की खाई कम हुई है और दोनों पक्ष एक साझा राजनीतिक लाइन पर आगे बढ़ने को तैयार हैं।

शशि थरूर पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उनके कुछ बयान भाजपा के पक्ष में जाते हैं। इस पर भी उन्होंने खुलकर सफाई दी। थरूर का कहना है कि वे किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार या भारत के रुख का समर्थन करते हैं। उनके मुताबिक, जब वे विदेश नीति या राष्ट्रीय हित से जुड़े मसलों पर बोलते हैं, तो वह एक भारतीय के तौर पर बोलते हैं, न कि केवल विपक्षी नेता के रूप में। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उनके बयानों को संदर्भ से काटकर पेश किया जाता है, जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। पिछले वर्षों में भारत-पाकिस्तान संबंधों या कुछ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर थरूर की टिप्पणियों ने कांग्रेस को असहज स्थिति में डाल दिया था। पार्टी के कुछ नेताओं ने तब यह सवाल उठाया था कि क्या थरूर पार्टी लाइन से हटकर बोल रहे हैं। अब थरूर ने इन विवादों को पीछे छोड़ते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी के भीतर उनकी प्रतिबद्धता को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि वे कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। थरूर ने यह भी साफ किया कि आगामी केरल विधानसभा चुनावों में वे पूरी ताकत के साथ कांग्रेस और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के लिए काम करेंगे। इस बयान के बाद पार्टी के भीतर उनकी भूमिका को लेकर तस्वीर और साफ हो गई है। केरल में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने भी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि शशि थरूर चुनावी अभियान में अग्रिम पंक्ति के नेता होंगे। पार्टी की रणनीति यह है कि थरूर को केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों पर ले जाया जाए और उनकी लोकप्रियता, बौद्धिक छवि और राष्ट्रीय पहचान का अधिकतम लाभ उठाया जाए।

कुल मिलाकर, गुरुवार की बैठक और शुक्रवार के बयान ने कांग्रेस के भीतर एक नई सियासी धारा का संकेत दिया है। जहां कुछ दिन पहले तक मतभेद, नाराजगी और दूरी की बातें सुर्खियों में थीं, वहीं अब एकजुटता और समन्वय का संदेश सामने आ रहा है। राहुल गांधी की तारीफ में थरूर के कसीदे केवल व्यक्तिगत बयान नहीं माने जा रहे, बल्कि इसे कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनके रिश्तों में आई नई गर्माहट के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह बदला हुआ माहौल केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर कांग्रेस की जमीनी राजनीति और चुनावी रणनीति में भी इसका असर दिखाई

असम की पहचान की जंग और घुसपैठ पर सियासी प्रहार

जीएनएस)। धेमाजी की धरती से शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम की राजनीति और जनसांख्यिकी को लेकर बड़ा और तीखा संदेश दिया। टकम मिसिंग पोरिन केबांग (ऑल मिसिंग स्टूडेंट्स यूनियन) द्वारा आयोजित 10वें मिसिंग यूथ फेस्टिवल के समापन समारोह में पहुंचे शाह ने न केवल कांग्रेस के लंबे शासनकाल पर सवाल उठाए, बल्कि राज्य की बदलती डेमोग्राफी को लेकर गंभीर चिंता भी जाहिर की। उनके भाषण का केंद्र बिंदु अवैध घुसपैठ, असम की सांस्कृतिक पहचान और आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को तीसरे कार्यकाल के लिए समर्थन की अपील रहा।

अमित शाह ने मंच से दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान असम की जनसांख्यिकी में ऐसा बदलाव आया, जिसने राज्य की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक संतुलन को हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा कि एक समय शून्य मानी जाने वाली अवैध घुसपैठ की संख्या कांग्रेस के लंबे शासन में बढ़ते-बढ़ते 64 लाख तक पहुंच गई। गृह मंत्री के अनुसार, इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य के सात जिलों में घुसपैठिए बहुमत में आ गए, जिससे स्थानीय आबादी, खासकर आदिवासी और मूल निवासी समुदायों को अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा।

शाह ने अपने संबोधन में कहा कि यह कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है, बल्कि असम की आत्मा से जुड़ा सवाल है। उनके मुताबिक, असम सिर्फ एक भौगोलिक राज्य नहीं, बल्कि विविध जातियों, जनजातियों और संस्कृतियों का संगम है, और जब डेमोग्राफी में असंतुलन आता है तो सबसे पहले यही विविधता खतरे में पड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चलते इस गंभीर मुद्दे को नजरअंदाज किया, जिसका खामियाजा आज असम की जनता को भुगतना पड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और असम में भाजपा की सरकार इस बदली हुई प्रवृत्ति को पलटने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दस वर्षों में, खासकर राज्य में लगातार दो भाजपा सरकारों के कार्यकाल के दौरान, अवैध घुसपैठियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है। शाह के अनुसार, अब तक 1.26 लाख एकड़ से अधिक भूमि को घुसपैठियों के कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है, जो यह दर्शाता है कि सरकार केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीन पर कार्रवाई कर रही है।

अपने भाषण में अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनावों को भी सीधे तौर पर इस मुद्दे से जोड़ दिया। उन्होंने जनता से अपील की कि यदि असम को घुसपैठ की समस्या से पूरी तरह मुक्त करना है, तो भाजपा को तीसरे कार्यकाल के लिए चुनना जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने साहसिक फैसले लिए हैं और केंद्र सरकार का पूरा समर्थन उन्हें हासिल है। शाह ने कहा कि तीसरा कार्यकाल केवल सत्ता का सवाल नहीं है, बल्कि असम की सुरक्षा, पहचान और भविष्य का प्रश्न है।

गृह मंत्री ने ऊपरी असम में घुसपैठ रोकने में मिसिंग समुदाय की भूमिका की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में घुसपैठियों का बस न पाना किसी हथियारबंद संघर्ष का नतीजा नहीं, बल्कि मिसिंग समुदाय की मेहनतकश जीवनशैली और सांस्कृतिक मजबूती का परिणाम है। शाह के शब्दों में, "घुसपैठ रोकने के लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं होती। आपकी मेहनत, आपकी खेती, आपकी जीवनशैली ही सबसे बड़ी दीवार है, जिसे पार करना घुसपैठियों के लिए आसान नहीं।"

अपने संबोधन में उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस शासन के दौरान कई आदिवासी समुदायों को अपनी पहचान बचाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। भूमि, भाषा और संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर इन समुदायों की आवाज को दबाया गया या नजरअंदाज किया गया। शाह ने भरोसा दिलाया कि मौजूदा भाजपा सरकार इस गलती को दोहराने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मिसिंग समुदाय सहित अन्य आदिवासी समाजों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वार्ताकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं और सरकार बातचीत के जरिए स्थायी समाधान निकालने के लिए तैयार है।

तमिलनाडु की सियासत में नई गर्माहट, डीएमके कांग्रेस गठबंधन की तस्वीर लगभग साफ

जीएनएस)। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और कांग्रेस के बीच चल रही अंदरूनी बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। लंबे समय से जिस खींचतान और असमंजस की चर्चा राजनीतिक गलियारों में थी, वह धीरे-धीरे खत्म होती नजर आ रही है। संकेत साफ हैं कि दोनों दल साथ-साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए लगभग तैयार हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द ही औपचारिक सहमति सामने आ सकती है।

दिल्ली से चेन्नई तक फैले राजनीतिक सूत्रों की मानें तो डीएमके और कांग्रेस के बीच मतभेद जितने सार्वजनिक तौर पर दिखाए जा रहे थे, उतने गहरे वास्तव में थे नहीं। दोनों ही दल यह समझते हैं कि तमिलनाडु में भाजपा और एआईएडीएमके के खिलाफ मजबूत लड़ाई के लिए गठबंधन की एकजुटता बेहद जरूरी है। यही वजह है कि बयानबाजी और दबाव की राजनीति के बावजूद, पर्दे के पीछे संवाद लगातार चलता रहा। अब यह संवाद समझौते की दिशा में आगे बढ़ चुका है।

गठबंधन की राह में आई इस नरमी का सबसे

बड़ा संकेत तब मिला, जब डीएमके सांसद कनिमोई ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात को केवल शिष्टाचार भेंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे गठबंधन की जमी बर्फ पिघलाने वाला अहम राजनीतिक कदम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बातचीत में न केवल सीटों के बंटवारे पर, बल्कि भविष्य में सत्ता संतुलन और आपसी तालमेल पर भी खुलकर चर्चा हुई। इसके बाद दोनों दलों के सुर बदले-बदले नजर आए और सार्वजनिक मंचों पर भी नरमी झलकने लगी।

कांग्रेस इस बार केवल सीटों तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी का मानना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा था और जिन सीटों पर उसे मौका मिला, वहां स्ट्राइक रेट भी मजबूत रहा। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से 18 पर जीत दर्ज की थी। इसी आधार पर पार्टी इस बार 35 से 40 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि यदि पार्टी को ज्यादा और प्रभावी सीटें मिलती हैं, तो वह गठबंधन की जीत में और बड़ी भूमिका निभा सकती है।

वहीं डीएमके की मजबूरी और रणनीति दोनों अलग-अलग स्तरों पर काम कर रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की पार्टी सत्ता में है और स्वाभाविक रूप से वह सीटों और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर ज्यादा उदार दिखना नहीं चाहती। दूसरी तरफ डीएमके यह भी जानती है कि कांग्रेस के बिना गठबंधन का राष्ट्रीय और वैचारिक संतुलन कमजोर पड़ सकता है। यही कारण है कि डीएमके कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए कुछ बड़े राजनीतिक संकेत देने को तैयार दिखाई दे रही है।

सूत्रों के अनुसार, डीएमके कांग्रेस को 25 से अधिक विधानसभा सीटें देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके साथ ही एक राज्यसभा सीट देने का प्रस्ताव भी चर्चा में है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को सम्मानजनक हिस्सेदारी का संदेश दिया जा सके। इतना ही नहीं, पुडुचेरी को लेकर भी एक दिलचस्प समीकरण उभर रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद देने के विकल्प पर भी बातचीत हुई है, जो गठबंधन को और मजबूत करने का बड़ा दांव हो सकता है। हालांकि सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। कांग्रेस की ओर से कैबिनेट में हिस्सेदारी की मांग लगातार उठाई जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिकम टगौर इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं और खुलकर कह चुके हैं कि कांग्रेस केवल समर्थन देने वाली पार्टी बनकर नहीं रहना चाहती। दूसरी ओर डीएमके फिलहाल इस मांग को टालती नजर आ रही है और उसका रुख यह है कि चुनाव के बाद परिस्थितियों के अनुसार फैसला लिया जाएगा। यह मुद्दा आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच सबसे बड़ा मोल-भाव का बिंदु बन सकता है।

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुंथगई ने संकेत दिए हैं कि सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी। उनका कहना है कि कांग्रेस अपने दावे तथ्यों और पिछले प्रदर्शन के आधार पर रखेगी। पार्टी नेतृत्व भी चाहता है कि यह बातचीत लंबी न खिंचे, ताकि चुनावी तैयारी समय रहते शुरू की जा सके। दूसरी ओर डीएमके भी यह नहीं चाहती कि गठबंधन को लेकर अनिश्चितता का संदेश जनता में जाए।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डीएमके और कांग्रेस दोनों एक-दूसरे की मजबूरी समझते हैं। डीएमके को एक ओर राज्य में अपनी सत्ता बचानी है, वहीं कांग्रेस को दक्षिण भारत में अपनी प्रासंगिकता मजबूत करनी है। ऐसे में समझौते का रास्ता ही दोनों के लिए सबसे व्यावहारिक विकल्प है। यही वजह है कि तमाम बयानबाजी के बावजूद, गठबंधन टूटने की आशंका अब लगभग खत्म होती दिख रही है।

कुल मिलाकर, तमिलनाडु की राजनीति में यह साफ संकेत मिल रहा है कि डीएमके और कांग्रेस एक बार फिर साथ मिलकर चुनावी रण में उतरेंगे।

पारदर्शिता पर खतरे की घंटी, मनरेगा के बाद अब आरटीआई को निशाने पर लेने का आरोप

जीएनएस)। नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने और अंततः खत्म करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। हालिया आर्थिक सर्वेक्षण में आरटीआई कानून की समीक्षा और सूचना रोकने के सुझावों को लेकर कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दिया है। खरगे ने सवाल उठाया कि जिस तरह समय-समय पर मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने की कोशिशें हुई हैं, क्या अब उसी क्रम में आरटीआई को भी खत्म करने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि सर्वेक्षण में 'मंत्रिस्तरीय वीटो' जैसे सुझाव यह संकेत देते हैं कि सरकार सूचना को जनता से दूर रखने का रास्ता तलाश रही है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सरकार नौकरशाहों की जवाबदेही से बचने के लिए आरटीआई कानून की आत्मा पर प्रहार करना चाहती है। उनके अनुसार, यदि पब्लिक सर्विस रिकॉर्ड, ट्रांसफर-पोस्टिंग और स्टाफ रिपोर्ट जैसी जानकारियों को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया, तो आम नागरिक के पास यह जानने का कोई जरिया नहीं बचेगा कि प्रशासन किस तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के बिना लोकतंत्र केवल नाम का रह जाता है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह जाती। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आरटीआई को एक झटके

में नहीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2019 में आरटीआई कानून में किए गए संशोधनों के जरिए सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन को सरकार के नियंत्रण में लाया गया। इससे सूचना आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं की स्वायत्तता खत्म हो गई और वे सरकार के दबाव में काम करने को मजबूर हो गईं। खरगे का कहना है कि जिन संस्थाओं को सरकार पर नजर रखने का जिम्मा सौंपा गया था, वही अब सरकार के अधीन हो चुकी हैं।

कांग्रेस ने 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023' को भी आरटीआई के कमजोर होने का बड़ा कारण बताया है। पार्टी का आरोप है कि सरकार 'निजता' की आड़ में जनहित से जुड़ी सूचनाओं को रोकने का रास्ता अपना रही है। खरगे के अनुसार, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े मामलों में जानकारी मांगने पर अब यह कहकर जवाब देने से इनकार किया जा सकता है कि वह निजी डेटा के दायरे में आती है। इससे सूचना के अधिकार की प्रभावशीलता लगभग समाप्त हो जाती है और जनता के सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। खरगे ने आंकड़ों के जरिए भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक आरटीआई से जुड़े 26 हजार से अधिक मामले लंबित हैं, जो यह दर्शाता है कि सरकार इस कानून को लागू करने के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग लंबे समय तक बिना मुख्य सूचना आयुक्त के काम करता रहा है और पिछले 11 वर्षों में यह सातवीं बार है जब यह अहम पद खाली छोड़ा गया। उनके मुताबिक, यदि सरकार वास्तव में पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध होती, तो ऐसे संवैधानिक पदों को खाली नहीं छोड़ा जाता।

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 2014 के बाद से 100 से अधिक आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। उनका आरोप है कि देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है, जहां सच बोलने और सवाल पूछने वालों को डराया जाता है। खरगे ने कहा कि जब सूचना मांगने वालों की जान तक सुरक्षित नहीं है और सरकार उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही, तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है।

अपने बयान के अंत में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आरटीआई केवल एक कानून नहीं, बल्कि आम नागरिक की ताकत है। इसे कमजोर करने का मतलब जनता की आवाज को दबाना है। कांग्रेस ने साफ किया है कि वह आरटीआई की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी और किसी भी कीमत पर इस कानून को खत्म नहीं होने देगी।

संपादकीय

अति आशावाद से बचें

देश में आम बजट से पहले सामने आने वाले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को लचीला व गतिशील बनाने पर बल दिया गया है। यह सर्वेक्षण उन चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है, जिनके लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद दर यानी जीडीपी के 7.4 रहने का भरोसा जताया गया है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकास वृद्धि दर के 6.8 से 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान में सीमापरक तनाव, व्यापार में व्यवधान और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता को भी ध्यान में रखा गया है। निश्चित रूप से यह सावधानीपूर्वक दर्शाया गया आशावादी दृष्टिकोण घरेलू मांग, उपभोग और निवेश की मजबूती को ही दर्शाता है। इसके बावजूद कि तमाम बाहरी जोखिम विद्यमान हैं, मसलन टैरिफ को लेकर आपूर्ति श्रृंखला में तनाव व देश की अपेक्षाओं का संतुलन बनाना शामिल है। यह सार्थक है कि सर्वेक्षण यथार्थवाद को नजरअंदाज नहीं करता है, जो यह भी दर्शाता है कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पूंजी प्रवाह व मुद्रा की ताकत से ही सफलता सुनिश्चित नहीं होती। यह भी हकीकत है कि एआई जैसी नई तकनीकों से होने वाले लाभ असमानता को ही बढ़ावा देते हैं। लेकिन इसके लिये भी सहायक मानव संसाधन और विनियामक ढांचे की जरूरत होती है। खासकर भारत जैसे देश में जहां श्रम शक्ति का बाहुल्य है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश होने का लाभ उठाएं। इसके लिये कौशल विकास को प्राथमिकता देने की सख्त जरूरत है, जिससे हम गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी उत्पादों के जरिये विश्व में आर्थिक स्पर्धा का मुकाबला कर सकें। ये कदम हमारे निर्यात बढ़ाने में भी सहायक हो सकते हैं। कालांतर में ये हमारे व्यापार घाटे को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है।

इसमें दो राय नहीं है कि हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के जरिये एक महत्वाकांक्षी रोड मैप बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत स्वदेशी अभियान को तरजीह देने से लेकर रणनीतिक लचीलेपन और रणनीतिक अनिवार्यता भारत की आर्थिक क्षमता की परीक्षा लेने वाला साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिये जरूरी है कि भारत में उत्पादित वस्तुओं की साख को अंतर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया जाए। निस्संदेह, विश्व में भारतीय उत्पाद 'खरीदने के बारे में सोचने' से स्थिति को 'बिना सोचे भारतीय उत्पाद खरीदने' वाली सोच विकसित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इस स्थिति के लिये हमें विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता की सख्त जरूरत होगी। निस्संदेह, हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ संपन्न हुए ऐतिहासिक समझौते को लेकर अर्थव्यवस्था में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जिसके अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर लंबे समय से लटके हुए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। सर्वेक्षण में इस बाबत कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में इस एफटीए के सिरे चढ़ने की उम्मीद है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ आम आदमी को कितना मिलता है। सवाल यह भी है कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ आम आदमी के जीवन को बदलने में कितना मददगार होगा। एआई और तकनीक क्रांति के दौर में भारतीय विपुल श्रम शक्ति का बेहतर उपयोग कैसे हो सकता है। भारत दुनिया में सबसे युवा श्रम शक्ति वाला देश है तो क्या हम उनकी योग्यता व क्षमता के अनुरूप रोजगार देने में सक्षम होंगे, ताकि वे विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दे सकें। जरूरत इस बात की है कि देश में बेरोजगारी की दर कम हो और युवाओं के विदेश पलायन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये पहल की जाए। वहीं दूसरी ओर फिसलन वाली जमीन पर चलते हुए सर्वेक्षण में दो दशक पुराने सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में बदलाव की मंशा जतायी गई है। निस्संदेह, ऐसे किसी बदलाव का आधार तार्किक होना चाहिए।

नाइट्रोजन चक्र बदलाव से अन्न-पेयजल संकट

"नया अध्ययन बताता है नाइट्रोजन चक्र परिवर्तन खाद्य उत्पादन, पानी की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और जलवायु स्थिरता को गहरे तक प्रभावित कर रहा है।

जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी पर कई परिवर्तन कर दिए हैं। इनमें से कई परिवर्तन ऐसे हैं जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं। बढ़ती गर्मी, बारिश के पैटर्न में बदलाव और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊंचे स्तर से फसलों को होने वाला नुकसान हमें दिखाई देता है लेकिन जलवायु के परिवर्तन समूची खाद्य प्रणालियों को कितना प्रभावित कर रहे हैं, इसका जरा भी अंदाजा हमें नहीं है। मिट्टी की सतह के नीचे और पौधों के ऊत्तकों के अंदर चुपचाप परिवर्तन हो रहा है। भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन की हलचल अब बदली हुई जलवायु परिस्थितियों पर तेजी से प्रतिक्रिया कर रही है। नाइट्रोजन में ये परिवर्तन खाद्य उत्पादन, पानी की सुरक्षा,पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और जलवायु स्थिरता को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी पर जीवन चक्र में नाइट्रोजन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह तत्व नाइट्रोजन प्रोटीन, एंजाइम और आनुवंशिक सामग्री बनाकर जीवन को सहारा देता है। पौधे पत्तियों,जड़ों और अनाज को उगाने के लिए मिट्टी से नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं। मिट्टी के जीवाणु जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से नाइट्रोजन को उपयोग योग्य रूपों में बदलते हैं। नाइट्रोजन का संतुलित प्रवाह स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र और अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। अतिरिक्त नाइट्रोजन हवा और पानी में चला जाता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है और गर्मी बढ़ाने वाली ग्रीनहाउस गैसें बनती हैं। दूसरी ओर,नाइट्रोजन की सीमित उपलब्धता फसलों के विकास को धीमा करने के साथ-साथ खाद्य आपूर्ति को भी कम कर देती है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन चक्र के बारे में एक नए अध्ययन में चीन के जेजान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मियाओ चंग का कहना है कि गर्म होती दुनिया में नाइट्रोजन खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक निर्णायक कारक बनती जा रही है। यह अध्ययन दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन नाइट्रोजन चक्रों को इस तरह से बदल रहा है जो या तो सतत विकास का समर्थन कर सकता है या पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण सीमाओं से परे धकेल सकता है। वैज्ञानिकों ने वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र मॉडल के साथ फील्ड में 30 वर्षों के प्रयोगों का विश्लेषण किया। उन्होंने इसमें विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में फसल भूमि, जंगलों और घास के मैदानों को सम्मिलित किया। उन्होंने उर्वरक, खाद, वायुमंडलीय जमाव और जैविक स्थिरीकरण के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ने वाली नाइट्रोजन पर गौर किया। फसल कटाई, गैस उत्सर्जन के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र से बाहर निकलने वाली नाइट्रोजन को भी मापा गया। इस विश्लेषण के असमान परिणाम सामने आए। कुछ स्थानों पर विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों में उत्पादकता में वृद्धि देखी गई जबकि अन्य क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कमी, प्रदूषण और पैदावार में कमी का अनुभव हुआ। नाइट्रोजन की असमान प्रतिक्रियाएं अब खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में वैश्विक अंतर को गहरा कर रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता नाइट्रोजन को प्रभावित करती है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर प्रकाश संश्लेषण में सुधार करके पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। गेहूं, चावल, मक्का और सोयाबीन सहित प्रमुख फसलों में अक्सर अधिक पैदावार देखी जाती है। अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की स्थितियों में जंगल और घास के मैदान भी पौधों की सामग्री का अधिक उत्पादन करते हैं। पानी के इस्तेमाल की बेहतर क्षमता पौधों को हल्के सूखे के स्ट्रेस से निपटने में मदद करती है। लेकिन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने पर पौधों के टिशू में नाइट्रोजन कम होती है। अनाज में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उसका पोषण मूल्य कम हो जाता है। पत्तियों और तनों में भी नाइट्रोजन की कमी दिखती है। दलहनी फसलें गैर-दलहनी प्रजातियों की तुलना में नाइट्रोजन की कमी का बेहतर प्रतिरोध करती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि लंबे समय तक नाइट्रोजन की कमी भविष्य की ग्रोथ और कार्बन स्टोरेज की क्षमता को कमजोर कर सकती है।

अध्ययन के सह-लेखक बाओजिंग गु ने कहा, ज्यादा कैलोरी का मतलब अपने आप बेहतर पोषण नहीं होता है। हम शायद ज्यादा बायोमास काट रहे हैं, लेकिन प्रति यूनिट नाइट्रोजन कम है, जो इंसानों के खाने और जानवरों के चारे दोनों के लिए मायने रखती है। गर्मी नाइट्रोजन के नुकसान को बढ़ाती है। बढ़ता तापमान नाइट्रोजन साइकलिंग को जटिल तरीकों से प्रभावित करता है। हल्की गर्मी जंगलों और घास के मैदानों में बढ़ने के मौसम को बढ़ाती है, जिससे पौधों की ग्रोथ बढ़ती है। खेती वाली जमीनें गर्मी के तनाव में ज्यादा जोखिम का सामना करती हैं। गर्म और शुष्क क्षेत्रों में मक्के की पैदावार तेजी से गिरती है। लगातार गर्मी के कारण कम अक्षांश वाले क्षेत्रों में गेहूं की पैदावार कम हो जाती है। अधिक तापमान मिट्टी में बैक्टीरिया और दूसरे जीवाणुओं की गतिविधि को तेज करता है। तेजी से अपघटन से नाइट्रोजन हवा और पानी में निकलती है। ऐसे में अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन काफी बढ़ जाता है। नाइट्रेट ज्यादा तेजी से भूजल और नदियों में मिल जाता है। ऐसी स्थितियों में वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पानी का प्रदूषण बढ़ जाता है। कम संसाधनों वाले क्षेत्रों को नाइट्रोजन की कमी और खाद्य असुरक्षा से ज्यादा नुकसान होता है।

बारिश के पैटर्न होने वाले बदलाव नाइट्रोजन के व्यवहार को बहुत ज्यादा नियंत्रित करते हैं। बढ़ी हुई बारिश पानी के स्ट्रेस को कम करके सूखे क्षेत्रों में पौधों की ग्रोथ में मदद करती है। शुष्क क्षेत्रों में घास के मैदान ठोस उत्पादकता लाभ के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। आर्द्र क्षेत्रों में ग्रोथ की प्रतिक्रियाएं छोटी होती हैं। लेकिन कम बारिश जीवाणु गतिविधि और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को सीमित करती है। नाइट्रोजन मिट्टी में फंसी रहती है जबकि पौधों की ग्रोथ धीमी हो जाती है। भारी बारिश नाइट्रेट को मिट्टी से बाहर निकालकर नदियों और झीलों में धकेल देती है, जबकि जलभराव वाली मिट्टी से नाइट्रोजन निकलती है। जैसे-जैसे बहुत अधिक बारिश की घटनाएं आम होती जा रही हैं, बड़े पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान का खतरा बढ़ रहा है।

वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में बताया कि जलवायु परिवर्तन नाइट्रोजन संतुलन में क्षेत्रीय अंतर को बढ़ा रहा है। इससे खाद्य असुरक्षित क्षेत्रों को ज़्यादा पैदावार के नुकसान और प्रदूषण के दबाव का सामना करना पड़ता है। सुदृढ़ नाइट्रोजन मैनेजमेंट पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करता है, साथ ही खाद्य उत्पादन में भी मदद करता है। कुशल उर्वरक का उपयोग नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में सुधार करता है। कार्बनिक और गैर रासायनिक खाद का उपयोग लंबे समय तक मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले पेड़ जंगलों को पोषक तत्वों की लगातार आपूर्ति बनाए रखने में मदद करते हैं।

नाइट्रोजन साइकिलिंग में प्रकाशित अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष है कि नाइट्रोजन को सिर्फ खेती के एक आवश्यक तत्व के तौर पर देखने के बजाय इसे वैश्विक पैमाने पर मैनेज करना शुरू करना होगा। अगर हम नाइट्रोजन को समझदारी से मैनेज करते हैं, तो हम एक ही समय में भुखमरी से निपटने, साफ पानी की रक्षा और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने में सक्षम हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि समन्वित कार्रवाई बढ़ते जलवायु परिवर्तन के तहत पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा कर सकती है, भोजन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है।

प्रेरणा

जब मन एक बिंदु बन जाए: एकाग्रता से जन्म लेती असाधारण क्षमता

मनुष्य की असली शक्ति उसके शरीर या साधनों में नहीं, बल्कि उसके मन की दिशा में छिपी होती है। जिस क्षण मन बिखरा हुआ होता है, उसी क्षण हमारी ऊर्जा व्यर्थ बहने लगती है। और जिस क्षण मन एक बिंदु पर ठहर जाता है, उसी क्षण साधारण व्यक्ति भी असाधारण परिणाम देने लगता है। एकाग्रता इसी ठहराव का नाम है। यह कोई रहस्यमय सिद्धि नहीं, बल्कि चेतना की वह अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह वर्तमान में समर्पित हो जाता है।

इंग्लैंड के प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक लॉर्ड मोनवर्न का जीवन इस सत्य का सशक्त उदाहरण है। वे ऐसे चिकित्सक थे जो भीड़-भाड़, शोर और दबाव के बीच भी अत्यंत जटिल ऑपरेशन पूर्ण सफलता के साथ कर लेते थे। जब किसी ने उनसे यह पूछा कि इतनी अव्यवस्था में वे विचलित क्यों नहीं होते, तो उनका उत्तर जितना सरल था, उतना ही गहन भी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के समय उनके साथ केवल तीन की उपस्थिति होती है—वे स्वयं, रोगी और उनका भगवान। इस कथन में एकाग्रता का संपूर्ण दर्शन समाहित है।

एकाग्रता का अर्थ है—अपने पूरे अस्तित्व के साथ किसी एक कार्य में उपस्थित होना। इसमें मन, बुद्धि और भाव—तीनों एक दिशा में प्रवाहित होते हैं। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम एक समय में कई काम करने को दक्षता समझते हैं, जबकि वास्तव में इससे हमारा ध्यान कमजोर होता जाता है। मन लगातार अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है, और वर्तमान क्षण केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। लॉर्ड मोनवर्न की एकाग्रता इसलिए अटूट थी क्योंकि वे वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से जीते थे।

उनके उत्तर में "भगवान" शब्द केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है। यह उस उच्च चेतना का संकेत है, जो व्यक्ति को उसके अहंकार से ऊपर उठाती है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि वह केवल कर्ता नहीं है, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य का माध्यम है, तब उसके भीतर विनम्रता जन्म लेती है। यही विनम्रता मन को हल्का करती है और एकाग्रता को गहरा बनाती है। चिकित्सक के लिए ऑपरेशन केवल तकनीकी कार्य नहीं था, बल्कि एक जीवन की जिम्मेदारी थी, और यही भावना उनके ध्यान को अडिग बनाए रखती थी।

एकाग्रता का सीधा संबंध भय से भी है। भय मन को भविष्य में ले जाता है—क्या होगा, अगर गलती हो गई तो, अगर परिणाम खराब हुआ तो। जब मन भय में डूबा होता है, तब वह वर्तमान में टिक नहीं पाता। लॉर्ड मोनवर्न का मन भय से मुक्त था, क्योंकि वे अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते थे और परिणाम को ईश्वर या प्रकृति की व्यवस्था पर छोड़ देते थे। यह भाव मन को तनाव से मुक्त करता है और कार्य को सहज बना देता है।

हम अक्सर यह सोचते हैं कि शांति तब आएगी जब परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी। लेकिन सच यह है कि परिस्थितियाँ कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होतीं। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अव्यवस्था, दबाव या शोर बना रहता है। शांति कोई बाहरी स्थिति नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था है। जब भीतर शांति होती है, तब बाहर की भीड़ भी हमें विचलित नहीं कर पाती। ऑपरेशन थिएटर की भीड़ लॉर्ड मोनवर्न के लिए बाधा नहीं थी, क्योंकि उनके भीतर स्पष्टता और मौन था। एकाग्रता का विकास अभ्यास से होता है। पहला अभ्यास है—स्पष्ट उद्देश्य। जब हमें यह स्पष्ट होता है कि हमें क्या करना है, तो मन भटकने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा अभ्यास है—सजगता। जब भी मन इधर-उधर भागने लगे, उसे कठोरता से नहीं, बल्कि शांति से वापस कार्य पर लाना चाहिए। तीसरा अभ्यास है—विश्वास। जब हम अपने प्रयास पर विश्वास रखते हैं और परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता नहीं करते, तब मन स्थिर रहता है।

एकाग्रता केवल बड़े और कठिन कार्यों तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर छोटे-बड़े क्षण में आवश्यक है। भोजन करते समय यदि हम पूरी तरह उपस्थित हों, तो न केवल भोजन का स्वाद बढ़ता है, बल्कि स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। बातचीत के समय यदि हम सामने वाले को ध्यान से सुनें, तो संबंधों में गहराई आती है। पढ़ते, लिखते या काम करते समय यदि मन एकाग्र हो, तो समय कम लगता है और परिणाम अधिक प्रभावशाली होते हैं। एकाग्रता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है—संवेदनशीलता। जब हम जिस कार्य को कर रहे हैं, उसके प्रति संवेदनशील होते हैं, तब ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। चिकित्सक के लिए रोगी केवल एक केस नहीं, बल्कि एक संवेदनशील जीवन था। यही संवेदना उनके हाथों को स्थिर और मन को सजग बनाए रखती थी। संवेदनशीलता अहंकार को कम करती है, और अहंकार के कम होते ही एकाग्रता सहज हो जाती है।

आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता इसी बात की है कि हम अपने ध्यान की गुणवत्ता को सुधारें। हमारे पास साधन, तकनीक और ज्ञान पहले से कहीं अधिक है, लेकिन ध्यान बिखरा हुआ है। यदि ध्यान एकाग्र हो जाए, तो वही साधन चमत्कारी परिणाम देने लगते हैं। एकाग्रता हमें यह सिखाती है कि कम कार्यों को, लेकिन पूरे मन से किया जाए।

अंत में, यह समझना आवश्यक है कि एकाग्रता कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं, बल्कि अनावश्यक विचारों से मुक्ति है। यह मन को बांधती नहीं, बल्कि मुक्त करती है। लॉर्ड मोनवर्न की सीख हमें यह बताती है कि यदि हम अपने कार्य में ईमानदारी, पूर्ण उपस्थिति और किसी उच्च उद्देश्य की भावना जोड़ दें, तो शोर, भीड़ और दबाव भी हमारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकते। जब मन एक बिंदु बन जाता है, तब साधारण जीवन भी असाधारण ऊँचाइयों को छूने लगता है। यही एकाग्रता की वास्तविक शक्ति और जीवन का सच्चा रहस्य है।

विकसित भारत के दृष्टिगत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मायने

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शाता है, जिसमें वैश्विक चुनौतियों के बावजूद उच्च वृद्धि दर का अनुमान है। देखा जाए तो यह बजट 2026-27 से पहले नीतिगत दिशा तय करता है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों पर जोर देता है। यही वजह है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वैसे नीतिगत सुधारों पर बल दिया गया है जो आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा दें। कहना न होगा कि ये सभी सुझाव वैश्विक चुनौतियों के बीच लचीलेपन और संरचनात्मक परिवर्तन पर केंद्रित हैं। जहां तक इस आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताओं की बात है तो इस सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि 7.4% और जीवीए 7.3% का प्रथम अनुमान दिया गया है, जबकि एफ वाई (FY) 2027 के लिए 6.8-7.2% का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। वहीं, निजी उपभोग (जीडीपी का 61.5%) और निवेश (30%) प्रमुख चालक हैं, साथ ही मुद्रास्फीति अप्रैल-दिसंबर 2025 में औसतन 1.7% रही। जबकि राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष (FY) 2026 में 4.4% तक कम होने का लक्ष्य है, जो नीतिगत स्थिरता दर्शाता है।

कुल मिलाकर आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख क्षेत्रीय प्रदर्शन इस प्रकार हैं- क्षेत्र - मुख्य उपलब्धियाँ

विनिर्माणः उच्च-तकनीकी गतिविधियों का 46.3% योगदान है; जबकि मोबाइल उत्पादन में 30 गुना वृद्धि (FY15-FY25) हुई है।

कृषिः खाद्यान्न उत्पादन 3577.3 लाख मीट्रिक टन हो चुका है; जबकि पशुपालन में 6.1% वृद्धि दर्ज की गई है।

सेवाएँः जीवीए में 9.3% वृद्धि (H1 FY26) हुई है; जबकि वैश्विक निर्यात में 4.3% हिस्सा हो चुका है।

बुनियादी ढांचाः राजमार्ग 60% बढ़े हैं; जबकि विदेशी मुद्रा भंडार $701.4 अरब पर पहुंच चुका है।

इस प्रकार ये आंकड़े उत्साहित करते हैं, क्योंकि जहां विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाऐं संघर्ष कर रही हैं, वही भारतीय अर्थव्यवस्था फर्राटे भर रही है। जहां तक आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के नीतिगत निहितार्थ की बात है तो यह सर्वेक्षण आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और रणनीतिक लचीलेपन पर जोर देता है, जिसमें पीएलआई (PLI) योजनाओं से 12.6 लाख नौकरियाँ सृजित हुईं हैं। यह ग्रामीण रोजगार में मनरेगा के स्थान पर 'विकसित भारत-जी राम जी' मिशन और एआई (AI) तथा स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस सुझाता है, जो रोजगार-सघन विकास को बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर, यह उच्च वृद्धि, कम महंगाई और समावेशी नीतियों से 2047 के विकसित भारत लक्ष्य को मजबूत बनाता है।

कहना न होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उन नीतिगत सुधारों पर जोर दिया गया है जो आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा दें। ये सुझाव वैश्विक चुनौतियों के बीच लचीलेपन और संरचनात्मक परिवर्तन पर केंद्रित हैं। यदि ग्रामीण रोजगार सुधार की दृष्टि से देखा जाए तो मनरेगा के स्थान पर 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025' की स्थापना का सुझाव दिया गया है, जो जवाबदेही बढ़ाएगा, अवसंरचना सुधरेगी और आय सुरक्षा मजबूत करेगा। यह ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के अनुरूप संरेखित करेगा।

वहीं, स्वदेशी और उत्पादन रणनीति के क्षेत्र में अनुशासित स्वदेशी अपनाने, निवेश लागत कम करने, उन्नत विनिर्माण मजबूत करने और रणनीतिक अपरिहार्यता की त्रिस्तरीय रणनीति का आह्वान किया गया है। जबकि राष्ट्रीय इनपुट लागत न्यूनीकरण रणनीति के तहत संसाधनों को किफायती बनाकर निर्यात और रोजगार बढ़ेगा। वहीं, एआई (AI) और प्रौद्योगिकी पर फोकस के तहत एआई (AI) को भारत की पूँजी, ऊर्जा और बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप अपनाने पर जोर दिया गया है, जबकि डेटा को रणनीतिक संसाधन मानते हुए घरेलू मूल्य बनाए रखने का ढांचा सुझाया गया।

वहीं, संप्रभु एआई (AI) बनाम एप्लीकेशन्स के ट्रेड-ऑफ बैलेंस करने की सिफारिश की गई है। जबकि ऊर्जा और पर्यावरण सुधार के दृष्टिगत राष्ट्रीय न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को 20,000 करोड़ आवंटन से 2047 तक 100 GW क्षमता का लक्ष्य ,निर्धारित किया गया है। जबकि सौर/पवन ट्रांजिशन के संसाधन तीव्रता पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई गई है। वहीं, PPP ढांचे को ट्रांजेक्शन-सेंट्रिक से सिस्टम-लेवल मार्केट बिल्डिंग की ओर ले जाना महत्वपूर्ण पहल है।

वहीं, अन्य प्रमुख सुझाव के दृष्टिगत श्रम कोड्स लागू कर 77 लाख नौकरियाँ सृजित करना और गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण फहल की गई है। जबकि डिजिटल कृषि मिशन, ई-नाम विस्तार और पीएम (PM) किसान जैसी योजनाओं से किसान आय सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया गया है। वहीं, संस्थागत क्षमता गहराई और संरचनात्मक सुधारों से संप्रभु रेटिंग सुधार जैसी दूरदर्शिता पूर्ण पहल की गई है। कहना न होगा कि इन नीतिगत सुधारों से आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

अभियान

शिव–शक्ति की कृपा का दिव्य संयोग: शुक्र प्रदोष व्रत में भक्ति से कैसे बदलता है भाग्य

भारतीय सनातन परंपरा में व्रत और पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, बल्कि वे जीवन को संतुलित, पवित्र और सकारात्मक दिशा देने के साधन होते हैं। इन्हीं व्रतों में प्रदोष व्रत का विशेष स्थान है। जब यह व्रत शुक्रवार के दिन आता है, तब इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। वर्ष 2026 में शुक्र प्रदोष का यह शुभ संयोग भक्तों के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है। यह व्रत भगवान शिव और शुक्र ग्रह—दोनों की संयुक्त कृपा पाने का दुर्लभ अवसर माना जाता है।

शुक्र प्रदोष व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है, बल्कि यह भौतिक जीवन में भी सुख, सौंदर्य, वैवाहिक आनंद और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल में की गई शिव पूजा सीधे महादेव के हृदय तक पहुँचती है। इस समय भगवान शिव अत्यंत करुणामय और शीघ्र फल देने वाले माने जाते हैं।

प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का वह समय होता है, जब दिन और रात का संगम होता है। यह संधि काल अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इसी समय भगवान शिव कैलास से पृथ्वी लोक की ओर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जो भक्त इस समय सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती।

शुक्रवार का संबंध शुक्र ग्रह से है, जो सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य, भोग-विलास, कला और वैवाहिक सुख का कारक माना जाता है। वहीं भगवान शिव को वैराग्य और करुणा का देवता कहा गया है। जब शुक्र और शिव का यह अद्भुत संयोग बनता है, तब जीवन में संतुलन आता है—भोग और योग का, संसार और साधना का।

शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव को यदि उनकी प्रिय वस्तुएँ अर्पित की जाएँ, तो पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन विशेष रूप से सफेद रंग की वस्तुओं का महत्व बताया गया है, क्योंकि सफेद रंग चंद्रमा, शुक्र और शिव—तीनों से जुड़ा हुआ है। सफेद रंग शांति, शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है।

इस दिन भगवान शिव को मिश्री, बर्फी या रसगुल्ले का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन मिठाइयों में दूध और शक्कर का समावेश होता है, जो मन और मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रह मजबूत होते हैं। इससे मानसिक शांति, प्रेम संबंधों में मधुरता और पारिवारिक जीवन में सौहार्द बढ़ता है।

शुक्र प्रदोष व्रत में केसर खीर का भोग भी विशेष महत्व रखता है। केसर को शुभता, ऐश्वर्य और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। दूध से बनी खीर स्वयं शिव को अत्यंत प्रिय है, और उसमें केसर का समावेश इसे और भी पवित्र बना देता है। मान्यता है कि इस दिन केसर खीर का भोग अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अविवाहित कन्याओं के लिए यह भोग विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि इससे मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति का योग बनता है और विवाह में आने वाली बाधाएँ दूर होती हैं।

पंचामृत का भोग शिव पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पंचामृत पाँच अमृत तत्वों का मिश्रण है—दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन पाँचों का अपना-अपना आध्यात्मिक अर्थ है। दूध शुद्धता और शांति का प्रतीक है, जो मन को निर्मल करता है। दही समृद्धि और संतान सुख का द्योतक माना गया है। घी शक्ति, विजय और तेज का प्रतीक है। शहद मधुर वाणी, एकता और आकर्षण का संकेत देता है। शक्कर सुखमय जीवन और संतोष का प्रतीक है। जब इन पाँचों को मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, तो जीवन के पाँच प्रमुख क्षेत्र—मन, शरीर, संबंध, धन और स्वास्थ्य—संतुलित होने लगते हैं।

प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को बेर अर्पित करने की भी विशेष परंपरा है। पुराणों में बताया गया है कि शिव जी को बेर अत्यंत प्रिय है। यह फल सरलता और भक्ति का प्रतीक है। बेर चढ़ाने का अर्थ है—अहंकार छोड़कर सरल भाव से ईश्वर के चरणों में समर्पण। मान्यता है कि इस दिन बेर अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। विशेषकर आर्थिक समस्याओं, ऋण बाधा और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए यह उपाय अत्यंत प्रभावी माना गया है।

शुक्र प्रदोष व्रत केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक फल तभी मिलता है, जब भक्त भीतर से भी शुद्ध हो। इस दिन वाणी में मधुरता, मन में करुणा और कर्म में संयम रखना विशेष पुण्यकारी माना गया है। शुक्रवार होने के कारण माता लक्ष्मी और देवी पार्वती का भी स्मरण करना शुभ होता है। माना जाता है कि देवी पार्वती की कृपा से ही शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं।

इस व्रत में संध्या समय दीपक जलाकर शिव मंत्रों का जप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। "ॐ नमः शिवाय" का जाप मन को स्थिर करता है और नकारात्मक विचारों को शांत करता है। प्रदोष काल में किया गया यह जप कई गुना फल प्रदान करता है। ऐसा विश्वास है कि इस समय किया गया एक मंत्र जप सामान्य समय के अनेक जपों के बराबर फल देता है।

शुक्र प्रदोष व्रत का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर विशेष रूप से देखा जाता है। जिन दंपतियों के जीवन में तनाव, कलह या दूरी है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। शिव और पार्वती को आदर्श दंपति माना गया है। उनकी पूजा करने से दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और समझ बढ़ती है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में शुक्र कमजोर होता है, उनके लिए यह व्रत शुक्र दोष को शांत करने का प्रभावी उपाय माना जाता है।

आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रदोष व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। शिव हमें त्याग और वैराग्य का मार्ग दिखाते हैं, जबकि शुक्र हमें सौंदर्य और आनंद का बोध कराता है। जब दोनों का समन्वय होता है, तब जीवन न तो अत्यधिक भोग में डूबता है और न ही कठोर वैराग्य में सूखता है। यही संतुलन जीवन को पूर्ण बनाता है।

अंततः शुक्र प्रदोष व्रत केवल मनोकामना पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मबोध का अवसर है। जब भक्त सच्चे मन से शिव की आराधना करता है, तो उसके भीतर धैर्य, शांति और विश्वास का संचार होता है। यही गुण धीरे-धीरे उसके भाग्य को भी बदलने लगते हैं। कहा गया है कि जब शिव प्रसन्न होते हैं, तो जीवन की कठिन से कठिन राह भी सरल हो जाती है।

इसलिए वर्ष 2026 में आने वाले शुक्र प्रदोष व्रत को केवल एक तिथि न समझें, बल्कि इसे शिव–शक्ति की कृपा पाने का दिव्य अवसर मानें। श्रद्धा, भक्ति और शुद्ध भाव से किया गया छोटा-सा प्रयास भी महादेव की अनंत कृपा का द्वार खोल सकता है। जब शिव का हाथ सिर पर होता है, तो सफलता स्वयं चलकर कदम चूमती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

राज्य के 2666 गाँवों को मिलेगा अपना ग्राम पंचायत घर

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में 663 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले ग्राम पंचायत घर-सह-पटवारी आवासों का एक साथ एक ही स्थान से ई-शिलान्यास करने का समारोह आयोजित हुआ

- गुजरात की सभी ग्राम पंचायतों को उनका अपना पंचायत घर देकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए सेचुरेशन के विचार को साकार कराने के लिए राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय
- मुख्यमंत्री ने आणंद के भादरण से 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' लॉन्च की
- पंचायत मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी तथा पंचायत राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महिडा की प्रेरक उपस्थिति
- तहसील मुख्यालय हो और नगर पालिका न हो; ऐसे 114 गाँवों को 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' के प्रथम चरण में समाविष्ट किया जाएगा, ऐसे गाँवों को शहरी समकक्ष सुविधा मिलने से उनका गुणात्मक एवं सर्वांगीण विकास होगा

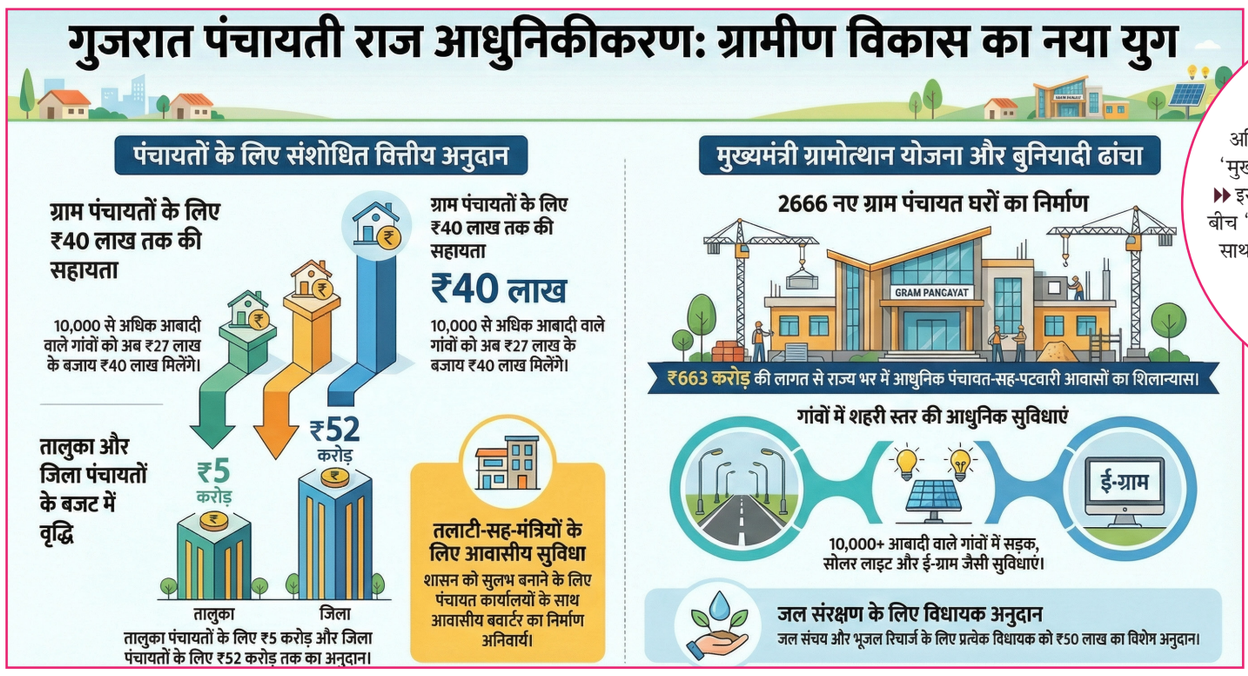

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को आणंद के भादरण में आयोजित समारोह से राज्य की 2666 ग्राम पंचायतों के लिए उनके अपने ग्राम पंचायत घर-सह-पटवारी आवासों का एक साथ एक ही स्थान से ई-शिलान्यास करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए गाँवों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो फोकस किया है, उसमें गुजरात अग्रसर रहने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस संदर्भ में श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का दिया गया सेचुरेशन अप्रोच गुजरात में साकार करने के लिए राज्य सरकार ने आगामी दिवसों में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को उनके अपने पंचायत घर-सह-पटवारी आवास देने का महत्वाकांक्षी निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन 2666 गाँवों में कुल 663 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले ग्राम पंचायत घर-सह-पटवारी आवासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण नागरिकों को स्थानीय स्तर से ही सरकारी सेवाएँ आसानी से उपलब्ध होंगी। उन्होंने इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण गृह निर्माण मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महिडा और अन्य महानुभावों की उपस्थिति में 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' की राज्यव्यापी लॉन्चिंग भी की।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य के 114 तहसील मुख्यालयों वाले ऐसे गाँव, जो तहसील मुख्यालय हैं; लेकिन नगर पालिका नहीं हैं, को 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' के प्रथम चरण में समाविष्ट कर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, पानी, स्वच्छता, सोलर स्ट्रीट लाइट, ई-ग्राम, कम्युनिटी हॉल आदि शहरी समकक्ष आधुनिक सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

उन्होंने जोड़ा कि शहरों पर बोझ कम हो तथा शहरों जैसी सुविधाएँ गाँवों में मिलें; इस आशय से आगामी समय में राज्य में 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' अंतर्गत लाने का राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसके फलस्वरूप ग्रामीण एवं शहरी विकास के बीच अंतर घटेगा तथा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का प्रधानमंत्री का मंत्र समग्र एवं संतुलित विकास से साकार होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विकास की राजनीति को गति देने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विजनरी लीडरशिप का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास का स्केल व स्पीड बढ़े हैं। शहरों में बढ़ते शहरीकरण के दबाव को संतुलित करने के लिए ग्रामीण विकास को केन्द्र में रखकर विशेष आयोजन किया जा रहा है। इसमें ग्राम पंचायतों के उत्थान के लिए केन्द्रित ऐसा कार्यक्रम राज्य में पहली बार आयोजित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए 'कैच द रेन' अभियान अंतर्गत वर्षा जल संचय तथा भूमिगत जल रिचार्ज के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हर विधायक को 50 लाख रुपए का विशेष अनुदान आवंटित किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर रिचार्जिंग व्यवस्थाएँ की जा सकें। मुख्यमंत्री ने गाय आधारित प्राकृतिक कृषि अपनाने की अपील करते हुए सभी से भूमि का स्वास्थ्य सुधारने तथा भावी पीढ़ी को निरोगी भविष्य देने का संकल्प लेने को कहा।

30 जनवरी शहीद दिवस तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने पूज्य बापू को हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि देकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों का भाव स्मरण किया। श्री पटेल ने कहा कि गांधीजी ने ग्राम स्वराज का संदेश देकर गाँवों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग दर्शाया था। उनकी यह विचारधारा आज भी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणास्रोत बनी है।

इस अवसर पंचायत एवं ग्रामीण गृह निर्माण मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि मृदु तथा दृढ़ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में 663 करोड़ रुपए की लागत से समग्र राज्य में 2666 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, जिससे गुजरात के गाँवों के विकास की नई दिशा मिलेगी।

उन्होंने इस अवसर पर भादरण के सरपंच श्री उदयभाई पटेल को गाँव के सर्वांगीण विकास के लिए अभिनंदन दिया तथा विभिन्न जिलों के गाँवों के उपस्थित सरपंचों से भादरण गाँव से प्रेरणा लेने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि समग्र राज्य में सरपंच तथा पटवारी-सह-मंत्री एक ही स्थान पर बैठकर गाँव के विकास के लिए ठोस कार्य कर सकें; इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 10 हजार से अधिक आधुनिक ग्राम सचिवालय बनाने की मंशा व्यक्त कर महात्मा गांधी के कथन 'गाँवों में भारत की आत्मा बसती है' को सही अर्थ में सार्थक किया है।

समारोह में उपस्थित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी ने महानुभावों का स्वागत करते हुए कहा कि आज का दिन गुजरात के ग्रामीण विकास के लिए गौरवपूर्ण है। राज्य की 2666 नई ग्राम पंचायतों के पंचायत घर-सह-पटवारी आवासों के ई-शिलान्यास तथा 114 गाँवों में 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' की लॉन्चिंग के साथ सुदूरवर्ती नागरिक तक सुविधाएँ पहुँचाने का सरकार का संकल्प साकार हो रहा है। उन्होंने इसके लिए प्रजाभिमुख प्रशासन से युक्त भादरण जैसे गाँव के चयन के लिए हर्ष की भावना व्यक्त की। साथ ही; उन्होंने भादरण गाँव के विकास मॉडल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस गाँव ने जन सहयोग तथा सुंदर प्रशासन द्वारा राज्य में एक नई राह दिखाई है। विशेषकर पानी के लिए मीटर सिस्टम लागू कर इस गाँव ने संसाधनों के कार्यक्षम उपयोग का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है।

इस अवसर पर जिला प्रभारी पंचायत राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महिडा, वित्त राज्य मंत्री कमलेशभाई पटेल, सांसद श्री मितेशभाई पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हसमुखभाई पटेल, जिला अग्रणी श्री संजयभाई पटेल, विधायक सर्वश्री विपुलभाई पटेल, योगेशभाई पटेल, पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री धनंजय द्विवेदी, विकास आयुक्त श्री हितेश कोया, जिला कलेक्टर श्री प्रवीण चौधरी, जिला विकास अधिकारी सुश्री देवहूति, जिला पुलिस अधीक्षक श्री गौरव जसाणी, निवासी अपर कलेक्टर श्री आर. एस. देसाई और बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों के गाँवों के सरपंच उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- आगामी समय में राज्य की 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाली सभी ग्राम पंचायतों तक 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' के विस्तार का लक्ष्य
- इस योजना के जरिये ग्रामीण एवं शहरी विकास के बीच 'समग्र तथा संतुलित' विकास का विजन 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र से साकार होगा
- महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की विचारधारा आज राष्ट्र निर्माण के संकल्प की प्रेरणास्रोत बनी है

भारतीय रेल की पहली LNG ट्रेन का सफल संचालन

जीएनएस)। मण्डल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने दिनांक 30.01.2026 को पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद स्थित इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो (ICD), साबरमती में भारतीय रेलवे की पहली एलएनजी-डीजल आधारित ड्यूल फ्यूल DEMU ट्रेन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस अभिनव पहल की विस्तृत जानकारी दी। उन्होने बताया कि भारतीय रेल ने स्वच्छ, पर्यावरण–अनुकूल एवं किफायती रेल परिचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय रेलवे में पहली बार डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (DEMU) के ड्राइविंग पावर कार (DPC) में लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) आधारित ड्यूल फ्यूल प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत 1400 एचपी के दो DEMU DPC को डीजल + एलएनजी ड्यूल फ्यूल प्रणाली में परिवर्तित किया गया है, जिसमें लगभग 40 प्रतिशत तक डीजल के स्थान पर

एलएनजी का उपयोग किया जा रहा है। इन दोनों परिवर्तित DPC पर 2000 किलोमीटर से अधिक का सफल फील्ड ट्रायल किया जा चुका है तथा वर्तमान में ये बिना किसी समस्या के नियमित यात्री सेवा में संचालित हो रहे हैं।

LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) ड्यूल फ्यूल प्रणाली के प्रमुख लाभ

1.पर्यावरणीय लाभ

- इंजन से निकलने वाले प्रदूषकों में उल्लेखनीय कमी, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (CO), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और पार्टिकुलेट मैटर (PM) में कमी।
- रेलवे मार्गों के आसपास वायु गुणवत्ता में सुधार तथा राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता।

2.ईंधन लागत में कमी

- एलएनजी, डीजल की तुलना में सस्ता है। आंशिक रूप से डीजल के स्थान पर एलएनजी के उपयोग से परिचालन लागत में उल्लेखनीय बचत होती है।
- परीक्षण आंकड़ों के आधार पर एक DPC से लगभग 11.9 लाख प्रति वर्ष की बचत तथा एक 8-कोच DEMU रेक (2 DPC) से लगभग 23.9 लाख प्रति वर्ष की बचत संभव है।

3.परिचालन में फ्लेक्सिबिलिटी

- ड्यूल फ्यूल इंजन, ईंधन की उपलब्धता के अनुसार डीजल और एलएनजी के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं, जिससे सेवा में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता।

4.प्रदर्शन में कोई कमी नहीं

- ड्यूल फ्यूल प्रणाली इस प्रकार डिजाइन की गई है कि इंजन की शक्ति और विश्वसनीयता पारंपरिक डीजल इंजन के समान बनी रहती है, जिससे बेहतर प्रदर्शन के साथ-साथ ईंधन बचत और प्रदूषण में कमी सुनिश्चित होती है। स्वीकृत डिजाइन के अनुसार DPC में लगभग 2200 लीटर क्षमता (लगभग 950–1000 किलोग्राम उपयोगी एलएनजी) का एलएनजी टैंक स्थापित किया गया है। एक बार पूर्ण भराव से 222 किलोमीटर के दैनिक संचालन के लिए पर्याप्त एलएनजी उपलब्ध हो जाता है, जिससे बार-बार ईंधन भरने की आवश्यकता कम होती है।

"मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" अभियान में स्काउट एण्ड गाइड की सक्रिय भागीदारी

जीएनएस)। रेल यात्रियों में टिकट खरीदने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के वाणिज्य विभाग द्वारा सभी मंडलों में 28 जनवरी 2026 से "मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" नामक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो 06 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। इस अभियान का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा 28.01.2026 को भावनगर टर्मिनस स्टेशन से किया गया। अभियान के अंतर्गत स्काउट एण्ड गाइड के सदस्यों द्वारा नारों, शाब्दिक संदेशों एवं नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे RailOne ऐप, एटीवीएम अथवा बुकिंग काउंटर से वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें। RailOne एक ऑल-इन-वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से यात्री आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट बुकिंग, लाइव ट्रेन स्थिति, PNR जानकारी,

भोजन सेवा तथा यात्री सहायता जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। स्काउट एण्ड गाइड के सदस्यों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि टिकट लेकर यात्रा करना न केवल एक कानूनी दायित्व है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान भी है। यात्रियों द्वारा खरीदे गए टिकटों से रेलवे का आर्थिक सुदृढ़ीकरण होता है, जिससे रेलगाड़ियाँ अधिक सुरक्षित एवं आधुनिक बनती हैं, यात्री सुविधाओं में सुधार होता है, रेल नेटवर्क का विस्तार होता है तथा स्टेशनों का कायाकल्प संभव हो पाता है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भावनगर मंडल के प्रमुख स्टेशनों—भावनगर टर्मिनस, वेरावल एवं जूनागढ़—पर यह अभियान विशेष रूप से संचालित किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर जागरूकता स्टॉल लगाए गए हैं, सेल्फी प्वाइंट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा बैनर एवं पोस्टर के माध्यम से यात्रियों को संदेश दिया जा रहा है। जूनागढ़ स्टेशन पर स्कूली बच्चों ने भी इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने यात्रियों को टिकट लेकर यात्रा करने हेतु प्रेरित किया तथा स्वयं भी सदैव वैध टिकट लेकर यात्रा करने का संकल्प लिया। इस अभियान में यात्रियों ने भी बढ़-चढ़कर सहभागिता की और अन्य यात्रियों से उचित यात्रा टिकट लेकर रेल यात्रा करने की अपील की।

वडोदरा - विरार सेक्शन पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक कमीशन,मुंबई (विरार) और अहमदाबाद रेलखंड हुआ कवच से पूर्ण सुरक्षित

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा रेल परिचालन में संरक्षा को और मजबूत करते के क्रम में 30 जनवरी,2026 को 344 किलोमीटर लंबे वडोदरा - विरार सेक्शन पर कवच 4.0 सिस्टम को सफलतापूर्वक कमीशन किया गया। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा इससे पहले दिसंबर 2025 में वडोदरा-अहमदाबाद सेक्शन पर कवच सिस्टम चालू किया था और आज मंडल द्वारा सूरत और वडोदरा सेक्शन पर इसे कमीशन किया गया है। इस प्रकार मुंबई (विरार) और अहमदाबाद रेलखंड कवच से लैस हो गया है।

वडोदरा के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने मुंबई से कवच सिस्टम के साथ चलने वाली पहली ट्रेन 20907 दादर - भुज सयाजी नगरी एक्सप्रेस के वडोदरा आगमन पर मीडिया को सम्बोधित करते हुए बताया कि पश्चिम रेलवे के नागदा-वडोदरा-सूरत-विरार-मुंबई सेंट्रल सेक्शन पर कवच को 397 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है। वडोदरा-सूरत-विरार सेक्शन पर काम जनवरी, 2023 में शुरू हुआ और आज इस सेक्शन में कवच कमीशन कर लिया गया है। 344 किलोमीटर लंबे विरार - वडोदरा खंड पर स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली 'कवच' प्रणाली के अंतर्गत 49 स्टेशनों को कवर किया गया है, 57 टावर स्थापित किये गए है और 688 किलो मीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गयी है। इस सेक्शन में इस प्रणाली के कमीशन होने से संरक्षा में वृद्धि के साथ साथ

उच्च गति पर भी सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित होगा।

उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विज़न को माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन में रेलवे में टेक्नोलॉजी में आत्मसात किया जा रहा है। कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम है, जो सिग्नल पास एट डेंजर (SPAD) की रोकथाम के साथ - साथ ऑटोमैटिक स्पीड कंट्रोल एवं आमने-सामने और पीछे से टक्करों से सुरक्षा जैसी कार्यक्षमताएं प्रदान करती है। यह ट्रैक पर RFID टैग और ट्रैक, सिग्नल और लोकोमोटिव के बीच कम्युनिकेशन के लिए अल्ट्रा-हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी (UHF) का इस्तेमाल करता है, जिससे केबिन में लोको पायलटों को रियल-टाइम जानकारी मिलती है, और यह सुरक्षित और ज़्यादा कुशल यात्राओं के लिए एक सतर्क रक्षक की तरह काम करता है।

वर्तमान में, कवच WAP-7 लोकोमोटिव पर सक्षम है। जल्द ही, इसे अन्य लोकोमोटिव पर भी शुरू किया जाएगा। लोकोमोटिव पर कवच लगाने का काम भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और अब तक WR पर कुल 364 लोकोमोटिव में कवच लगाया जा चुका है। वडोदरा-नागदा पर काम पूरी तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद है कि यह मार्च, 2026 तक इसे पूरा कर लिया जायेगा। पश्चिम रेलवे जल्द से जल्द पूरे BG रूट पर कवच का काम पूरा करने के लिए तैयार है।

भावनगर रेलवे मंडल पर शहीद दिवस के अवसर पर दो मिनट का मौन रखकर वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि

जीएनएस)। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की स्मृति में पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल पर 30 जनवरी 2026 को शहीद दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंडल कार्यालय, रेलवे स्टेशनों, हेल्थ यूनिटों तथा कोचिंग डिपो सहित मंडल के सभी प्रतिष्ठानों में प्रातः 11.00 बजे दो मिनट का मौन रखकर वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शहीद दिवस के उपलक्ष्य में मंडल कार्यालय में मौन अवधि के प्रारंभ एवं समाप्ति पर सायरन बजाकर सभी विभागीय कर्मचारियों को सचेत किया गया, जिससे कार्यक्रम का अनुशासित एवं गरिमामय आयोजन सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर मंडल कार्यालय के लॉबी में मंडल रेल

प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा सहित मंडल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने एकत्र होकर दो मिनट का मौन रखकर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शहीदों के बलिदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन और कार्य में अपनाने का संकल्प भी लिया।

गुजरात की 'स्वतंत्रता का मंत्र : वंदे मातरम्' थीम आधारित झाँकी को 'पॉपुलर चॉइस श्रेणी' में प्रथम स्थान का पुरस्कार नई दिल्ली में विधिवत् रूप से प्रदान किया गया

- गुजरात राज्य की ओर से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे तथा सूचना आयुक्त श्री किशोर बचाणी ने ट्रॉफी स्वीकार की
- लगातार चार वर्ष पॉपुलर चॉइस पुरस्कार के साथ वर्ष 2024 में जूरीस चॉइस पुरस्कार सहित गुजरात को चार वर्ष में कुल 5 पुरस्कार मिले

जीएनएस)। गांधीनगर : 77वें गणतंत्र पर्व के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में गुजरात की झाँकी को लगातार चौथी बार 'पॉपुलर चॉइस श्रेणी' में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए शुक्रवार को विधिवत् रूप से ट्रॉफी एवं पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ के करकमलों से प्रदान किए गए ट्रॉफी एवं प्रमाणपत्र को गुजरात राज्य की ओर से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे तथा सूचना आयुक्त श्री किशोर बचाणी ने स्वीकार किया।

इसके साथ ही; झाँकी निर्माण की प्रक्रिया के समय राष्ट्रीय रंगशाला में आयोजित विभिन्न राज्यों के कलाकारों के सांस्कृतिक नृत्यों की प्रतियोगिता में

गुजरात के नृत्य को प्रोत्साहक पुरस्कार प्राप्त हुआ।

यहाँ उल्लेखनीय है कि 'स्वतंत्रता का मंत्र : वंदे मातरम्' विषय पर आधारित इस वर्ष की झाँकी का गुजरात सरकार के सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्माण किया गया था।

सूचना आयुक्त श्री किशोर बचाणी के दिशादर्शन तथा अपर सूचना निदेशक श्री अरविंद पटेल के मार्गदर्शन में संयुक्त सूचना निदेशक डॉ. संजय कचोट एवं फिल्म प्रोडक्शन शाखा की सूचना उप निदेशक सुश्री भावना वसावा द्वारा इस झाँकी के निर्माण का समग्र कार्य किया गया था।

इससे पहले वर्ष 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकतम् उपयोग के आह्वान को साकार करने में गुजरात की पहल के रूप में प्रस्तुत की गई 'क्लीन ग्रीन एनर्जीयुक्त गुजरात' झाँकी को 'पॉपुलर चॉइस श्रेणी' में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके साथ शुरू हुई विजय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2024 में प्रस्तुत की गई गुजरात की 'धोरडो : वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज' थीम आधारित झाँकी ने 'पॉपुलर चॉइस श्रेणी' में पुरस्कार प्राप्त करने के साथ-साथ झाँकियों की श्रेष्ठता की चयन समिति की 'जूरीस चॉइस' श्रेणी में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में गुजरात ने आधुनिक विकास की जो लंबी छलांग लगाई है, उसकी विकास गाथा तथा प्राचीन विरासत की झाँकी दर्शाने वाली 'अनार्तपुरथी एकतानगर सुधी – विरासतथी विकासनो अद्भुत संगम' झाँकी ने 'पॉपुलर चॉइस पुरस्कार' जीता। इसके बाद लगातार चौथे वर्ष इस श्रेणी में वर्ष 2026 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर गुजरात ने इतिहास रचा है।

पश्चिम रेल्वे

शुध्धिपत्र

टेंडर नंबर IND/UJN/SIMHASTHA/01 का पहला शुद्धिपत्र। NIT में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। NIT में पहले से छपा हुआ: डिप्टी चीफ इंजीनियर (कंस्ट्रक्शन)I, वेस्टर्न रेलवे, इंदौर (MP) दिए गए विवरण के अनुसार ई-टेंडरिंग टू-पैकेट सिस्टम और टू-स्टेज रिवर्स नीलामी के माध्यम से टेंडर आमंत्रित करते हैं। अब इसे इस प्रकार पढ़ा जाए: डिप्टी चीफ इंजीनियर (कंस्ट्रक्शन)I, पश्चिम रेलवे, इंदौर (MP) दिए गए विवरण के अनुसार ई-टेंडरिंग टू-पैकेट सिस्टम के माध्यम से टेंडर आमंत्रित करते हैं। अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 1077

हमें ट्राइक करें: facebook.com/WesternRly

वन भूमि पर बने धार्मिक ढांचे को लेकर बढ़ा विवाद दस्तावेज न मिलने पर ध्वस्तीकरण के संकेत

जीएनएस)। इटावा जिले में वन विभाग की भूमि पर बनी एक मजार को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई और सामाजिक प्रतिक्रिया के बीच तनाव का माहौल बन गया है। फिशर वन क्षेत्र में स्थित इस मजार को वन विभाग ने अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए हैं। विभाग का दावा है कि यह धार्मिक ढांचा सरकारी वन भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के बनाया गया है और संबंधित पक्ष द्वारा स्वामित्व से जुड़े कोई भी दस्तावेज अब तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसी आधार पर नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह भूमि अभिलेखों में स्पष्ट रूप से वन क्षेत्र के रूप में दर्ज है और यहां किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण कानूनन प्रतिबंधित है।

जिला वन अधिकारी विकास नायक का कहना है कि वन रेंज अधिकारी के माध्यम से मजार की देखरेख करने वाले व्यक्ति को विधिवत नोटिस दिया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि भूमि स्वामित्व या वैध निर्माण से संबंधित दस्तावेज तय समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो विभाग को मजबूरन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ेगी। अधिकारियों का कहना है कि नोटिस दिए जाने के बाद भी कोई संतोषजनक साक्ष्य सामने नहीं आया है।

वन विभाग यह भी स्पष्ट कर रहा है कि यह कार्रवाई किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं की जा रही है, बल्कि यह वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने और कानून का पालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया

का हिस्सा है। विभाग का तर्क है कि यदि एक मामले में छूट दी जाती है, तो इससे भविष्य में अन्य अतिक्रमणों को भी बढ़ावा मिल सकता है, जिससे वन क्षेत्र और पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा।

हालांकि, प्रशासनिक रुख के विपरीत स्थानीय मुस्लिम समाज में इस कार्रवाई को लेकर गहरा असंतोष व्याप्त है। समुदाय के लोगों का कहना है कि यह मजार दशकों से क्षेत्र में आस्था का केंद्र रही है। यहां हर गुरुवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के गांवों और कस्बों से लोग शामिल होते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह मजार केवल एक धार्मिक ढांचा नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान से भी जुड़ी हुई है।

समाज के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि प्रशासन को पहले मजार के ऐतिहासिक और धार्मिक पहलुओं की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और किसी भी निर्णय से पहले सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि वर्षों से चली आ रही धार्मिक गतिविधियों को अचानक अवैध बताकर समाप्त करना सामाजिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं होगा।

इस विवाद को और जटिल बनाता है मजार से जुड़ा ऐतिहासिक दावा। स्थानीय स्तर पर यह कहा जाता है कि यह मजार मुगल आक्रांता मोहम्मद गौरी के सेनापति शमशुद्दीन से संबंधित है। मुस्लिम समाज के लोग इसे 'बीहड़ वाले सैयद बाबा' की मजार के नाम से जानते हैं और मानते हैं कि यह स्थान लंबे समय से श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहा है। दूसरी ओर, इतिहासकारों और प्रशासनिक अभिलेखों में इस दावे की पुष्टि करने वाले ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। वन विभाग भी यही कह रहा है कि अब तक की जांच में मजार के निर्माण या उसके ऐतिहासिक स्वरूप से संबंधित कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं मिला है।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि मामला संवेदनशील है और इसे कानून के दायरे में रहकर ही सुलझाया जाएगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि यदि संबंधित पक्ष भविष्य में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, तो वन संरक्षण अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई अपरिहार्य होगी।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आस्था और कानून के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। एक ओर राज्य का दायित्व है कि वह सरकारी और वन भूमि की रक्षा करे, वहीं दूसरी ओर वर्षों से चली आ रही धार्मिक परंपराओं और भावनाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल स्थिति यह है कि प्रशासन अपनी कानूनी प्रक्रिया पर अडिग है और स्थानीय समुदाय अपनी आस्था के संरक्षण के लिए आवाज उठा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन इस विवाद का समाधान किस दिशा में करता है और क्या कोई ऐसा रास्ता निकल पाता है, जिससे कानून का पालन भी हो और सामाजिक सौहार्द भी बना रहे।

ऊर्जा के वैश्विक विमर्श में भारत की निर्णायक मौजूदगी

जीएनएस)। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के समापन अवसर पर जब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की भूमिका पर अपनी बात रखी, तो यह केवल एक औपचारिक वक्तव्य नहीं था, बल्कि बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में भारत की बढ़ती ताकत और भरोसे का स्पष्ट संकेत था। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि आज भारत वैश्विक ऊर्जा मंच पर पहले से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में खड़ा है और दुनिया में बढ़ती भू-राजनीतिक अस्थिरताओं के बावजूद भारत का फोकस ऊर्जा सुरक्षा, किफायती आपूर्ति और सतत विकास पर केंद्रित है। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, राजनीतिक तनाव और आपूर्ति संकट ने ऊर्जा बाजार को अस्थिर बना दिया है।

हरदीप सिंह पुरी ने यह स्पष्ट किया कि भारत ने बीते वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में जो नीतिगत और संरचनात्मक सुधार किए हैं, वही आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल ऊर्जा आयात पर निर्भर रहने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद हिस्सा बन चुका है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, जो उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विस्तार को दर्शाता है। इसके साथ ही भारत चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर भी है और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में अग्रणी देशों में शामिल है। यह उपलब्धियां इस बात का प्रमाण हैं कि भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में केवल मांग ही नहीं बढ़ाई, बल्कि आपूर्ति और प्रसंस्करण की अपनी क्षमता को भी लगातार सशक्त किया है।

मंत्री ने अपने संबोधन में यह भी रेखांकित किया कि वैश्विक स्तर पर जब ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है, तब

भारत ने विविध स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने की रणनीति अपनाई है। कच्चे तेल और गैस के आयात में स्रोतों का विविधीकरण, दीर्घकालिक समझौते और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना भारत की उस दूरदर्शी नीति का हिस्सा है, जिसने उसे किसी एक क्षेत्र या देश पर निर्भर रहने से बचाया है। इसी वजह से वैश्विक संकटों के बावजूद भारत अपने नागरिकों और उद्योगों को अपेक्षाकृत स्थिर और किफायती ऊर्जा उपलब्ध कराने में सफल रहा है।

इंडिया एनर्जी वीक को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह मंच केवल एक सम्मेलन भर नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा भविष्य को आकार देने का एक सशक्त माध्यम है। इस आयोजन के जरिए सरकारी प्रतिनिधि, उद्योग जगत के नेता, निवेशक और नवप्रवर्तक एक साथ आते हैं और ऊर्जा से जुड़े जटिल मुद्दों पर संवाद करते हैं। यहां नीति, निवेश और तकनीक के बीच तालमेल स्थापित होता है, जिससे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि भारत इस मंच के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि वह सहयोग और संवाद में विश्वास करता है, टकराव में नहीं।

पुरी ने अपने संबोधन में किफायती ऊर्जा के महत्व पर भी विशेष जोर दिया। उनका कहना था कि ऊर्जा केवल आर्थिक विकास का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता और जीवन स्तर को बेहतर बनाने का आधार भी है। अगर ऊर्जा महंगी होगी, तो उसका सीधा असर आम आदमी, किसानों और छोटे उद्योगों पर पड़ेगा। इसलिए भारत की नीति यह सुनिश्चित करने की है कि ऊर्जा न केवल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, बल्कि उसकी कीमत भी आम लोगों की पहुंच में रहे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ईंधन और स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैश्विक ऊर्जा रणनीतियों में भारत की सक्रिय भागीदारी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार की जा रही है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत केवल अपनी जरूरतों की बात नहीं करता, बल्कि वैश्विक दक्षिण की चिंताओं और अपेक्षाओं को भी मंचों पर मजबूती से रखता है। विकासशील देशों के सामने ऊर्जा सुरक्षा और किफायती आपूर्ति एक बड़ी चुनौती है और भारत इस चुनौती को समझते हुए समाधान का हिस्सा बनना चाहता है। यही कारण है कि आज भारत की राय और अनुभव को वैश्विक ऊर्जा नीतियों में गंभीरता से सुना जा रहा है।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में भारत ऊर्जा क्षेत्र में और बड़े निवेश, नई तकनीकों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के जरिए अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। ऊर्जा संक्रमण के इस दौर में भारत खुद को एक ऐसे सेतु के रूप में स्थापित कर रहा है, जो पारंपरिक ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़े। यह संतुलित दृष्टिकोण ही भारत को अन्य देशों से अलग पहचान देता है।

अहमदाबाद-तिरुच्चिरापल्ली और हापा-नाहरलगुन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद-तिरुच्चिरापली साप्ताहिक स्पेशल और हापा-नाहरलगुन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे विशेष किराये पर विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09419 अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली साप्ताहिक स्पेशल, जिसे 26 फरवरी, 2026 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 तक कर दिया गया है।

ट्रेन संख्या 09420 तिरुचिरापल्ली-अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल जिसे 01 मार्च, 2026 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब बढ़ाकर 03 जनवरी, 2027 तक कर दिया गया है। ट्रेन संख्या 09525 हापा-नाहरलगुन स्पेशल, जिसे 25 फरवरी, 2026 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब बढ़ाकर 30 दिसंबर,

2026 तक कर दिया गया है।

ट्रेन संख्या 09526 नाहरलगुन-हापा स्पेशल, जिसे 28 फरवरी, 2026 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब बढ़ाकर 02 जनवरी, 2027 तक कर दिया गया है।

ट्रेन संख्या 09419 और 09525 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 01 फरवरी, 2026 से पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी।

ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा विरार–सूरत–वडोदरा खंड पर कवच 4.0 को कमीशन किया गया

ट्रेन संख्या 20907 दादर–भुज सायाजीनगरी एक्सप्रेस मुंबई से चलने वाली पहली कवच-सुसज्जित ट्रेन बनी

जीएनएस)। स्वदेशी ट्रेन संरक्षण प्रणाली के यात्री सेवाओं के लिए शुरू होने से रेल संरक्षा में एक बड़ा कदम यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन उत्कृष्टता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करते हुए पश्चिम रेलवे ने 344 किलोमीटर लंबे विरार–सूरत–वडोदरा खंड पर यात्री ट्रेनों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन संरक्षण प्रणाली कवच संस्करण 4.0 को कमीशन कर दिया है। 30 जनवरी, 2026 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई, जब ट्रेन संख्या 20907 दादर–भुज सायाजीनगरी एक्सप्रेस मुंबई से चलने वाली पहली कवच-सुसज्जित ट्रेन बनी। यह पश्चिम रेलवे नेटवर्क पर उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगिकी के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विरार–सूरत–वडोदरा खंड के 344

किलोमीटर लंबे मार्ग पर कवच प्रौद्योगिकी को कमीशन किया गया है। इस कॉरिडोर पर कवच को 49 स्टेशनों पर लागू किया गया है, जिसे 57 रेडियो संचार टावरों तथा लगभग 700 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल का सहयोग प्राप्त है। कवच एक अतिरिक्त सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है, जो सिगनल का खतरे की स्थिति में पार होना, अधिक गति तथा टक्करों जैसी मानवीय त्रुटियों से उत्पन्न जोखिमों को न्यूनतम करने में सहायक है। साथ ही, लेवल क्रॉसिंग पर स्वचालित सीटी (ऑटो-व्हिसलिंग) और लोको पायलट के केबिन में सिगनल पहलू की पुनरावृत्ति जैसी विशेषताओं के माध्यम से प्रतिकूल मौसम और कम दृश्यता की परिस्थितियों में भी परिचालन सुरक्षा को और सुदृढ़ करता है।

पश्चिम रेलवे द्वारा इससे पूर्व दिसम्बर 2025 में वडोदरा–अहमदाबाद खंड पर कवच प्रणाली को कमीशन किया गया था। विरार–वडोदरा खंड के कमीशन होने के साथ ही, वर्तमान में पश्चिम रेलवे पर कुल 435 रूट किलोमीटर में कवच प्रणाली लागू की जा चुकी है।

श्री विनीत ने आगे कहा कि भारतीय रेल

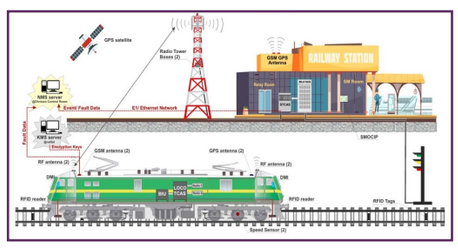

द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कवच प्रौद्योगिकी एक तकनीकी रूप से उन्नत एवं लागत-प्रभावी सुरक्षा समाधान है, जो रेलवे सुरक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है।

पहले से कमीशन किए गए खंडों के अतिरिक्त, पश्चिम रेलवे के 2667 रूट किलोमीटर को कवर करने वाले अन्य कई खंडों पर कवच कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 1435 करोड़ है। इसके अलावा, 2476 मार्ग किलोमीटर पर कवच कार्यों के लिए स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किए गए हैं, जो इस कार्यक्रम के व्यापक स्तर और तीव्र गति को दर्शाते हैं। चरणबद्ध क्रियान्वयन के साथ, पश्चिम रेलवे अपने संपूर्ण ब्रॉड गेज नेटवर्क पर कवच के विस्तार की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिससे समग्र रेल सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के प्रति उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पुनः पुष्ट होती है। अपने नेटवर्क पर उन्नत सुरक्षा प्रणालियों की तैनाती में निरंतर प्रगति के साथ पश्चिम रेलवे देश के लिए एक अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और भविष्य-तैयार रेलवे प्रणाली के निर्माण की दिशा में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रहा है।

पश्चिम रेलवे द्वारा 1 फरवरी 2026 को चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल के बीच जम्बो ब्लॉक

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा रविवार, 1 फरवरी 2026 को चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन फास्ट लाइनों पर ट्रैक, सिगनलिंग प्रणाली तथा ओवरहेड उपकरणों के अनुरक्षण हेतु जम्बो ब्लॉक लिया जायेगा। यह ब्लॉक 10:35 बजे से 15:35 बजे तक कुल पाँच घंटे को होगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान सभी फास्ट लाइन की ट्रेनें चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच स्लो लाइनों पर चलाई जाएँगी। इसके अलावा, कुछ अप एवं डाउन उपनगरीय सेवाएँ निरस्त रहेंगी, जबकि चर्चगेट की ओर जाने वाली कुछ ट्रेनों को बांद्रा/दादर पर ही शॉर्ट-टर्मिनेट कर वहीं से रिटर्न चलाया जाएगा। प्रभावित ट्रेनों की विस्तृत सूची उपनगरीय खंड के सभी स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध रहेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखें और तदनुसारद अपनी यात्रा की योजना बनाएँ।

पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न गंतव्यों के बीच दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के बीच चल रही दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09085/09086 मुंबई सेंट्रल – इंदौर त्रि-साप्ताहिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 09085 मुंबई सेंट्रल – इंदौर त्रि-साप्ताहिक स्पेशल को 27 फरवरी,

2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09086 इंदौर – मुंबई सेंट्रल त्रि-साप्ताहिक स्पेशल को 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। 2. ट्रेन संख्या 09057/09058 सूरत – मंगलुरु द्वि-साप्ताहिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 09057 सूरत – मंगलुरु द्वि-साप्ताहिक स्पेशल को 25 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09058 मंगलुरु – सूरत द्वि-साप्ताहिक स्पेशल को 26 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, ट्रेन संख्या 09057 सूरत – मंगलुरु स्पेशल के समय में संशोधन किया गया है और अब यह ट्रेन सूरत से 19:40 बजे के बजाय 19:35 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09058 मंगलुरु – सूरत स्पेशल अब मंगलुरु से 22:10 बजे के बजाय 22:30 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेन संख्या 09085, 09086 एवं 09057 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 31 जनवरी, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भारत की तिजोरी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, विदेशी मुद्रा भंडार ने रचा नया इतिहास

जीएनएस)। नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनावों और बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच भारत की आर्थिक मजबूती का एक और बड़ा प्रमाण सामने आया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 709.41 अरब डॉलर हो गया, जो अपने आप में एक नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। इससे पहले सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचा था, जिसे उस समय ऐतिहासिक माना गया था, लेकिन मौजूदा आंकड़ों ने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सिर्फ एक सप्ताह के भीतर विदेशी मुद्रा भंडार में 8.05 अरब डॉलर की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं मंदी, महंगाई और कर्ज के दबाव से जूझ रही हैं। इससे ठीक एक सप्ताह पहले भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 14.16 अरब डॉलर की तेज बढ़ोतरी देखी गई थी, जिसके बाद कुल भंडार 701.36 अरब डॉलर तक पहुंच गया था।

सोना वायदा 9903 रुपये और चांदी वायदा 47987 रुपये लुढ़का: क्रूड ऑयल वायदा 33 रुपये फिसला

कमोडिटी वायदाओं में 101068 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 67529 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 86951 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 46400 पॉइंट के स्तर पर

मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 168610.81 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 101068.42 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 67529.56 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 46400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3137.37 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 86951.70 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 167899 रुपये के भाव पर खूलकर, 168000 रुपये के दिन के उच्च और 159239 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 169403 रुपये के पिछले बंद के सामने 9903 रुपये या 5.85 फीसदी की गिरावट के साथ 159500 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 8569 रुपये या 5.76 फीसदी लुढ़ककर 140298 रुपये प्रति 8 ग्राम बोला गया। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 1066 रुपये या 5.69 फीसदी लुढ़ककर 17680 रुपये प्रति 1 ग्राम बोला गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 168990 रुपये के भाव पर खूलकर, 170954 रुपये के दिन के उच्च और 160697 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 10257 रुपये या 6 फीसदी लुढ़ककर 160697 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 182600 रुपये के भाव पर खूलकर, 185000 रुपये के दिन के उच्च और 173360 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 184425 रुपये के पिछले बंद के सामने 7806 रुपये या 4.23 फीसदी लुढ़ककर 176619 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 383898 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 389986 रुपये और नीचे में 351906 रुपये पर पहुंचकर, 399893 रुपये के पिछले बंद के सामने 47987 रुपये या 12 फीसदी लुढ़ककर 351906 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 47912 रुपये या 11.67 फीसदी औंधकर 362792 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 48277 रुपये या 11.74 फीसदी गिरकर 362782 रुपये

प्रति किलो हुआ। मेटल वर्ग में 9707.35 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 73.5 रुपये या 5.21 फीसदी औंधकर 1338 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 12.3 रुपये या 3.61 फीसदी घटकर 328.45 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 13.65 रुपये या 4 फीसदी लुढ़ककर 327.85 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 7.05 रुपये या 3.5 फीसदी लुढ़ककर 194.6 रुपये प्रति किलो बोला गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2590.66 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5938 रुपये के भाव पर खूलकर, 6001 रुपये के दिन के उच्च और 5896 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 33 रुपये या 0.55 फीसदी गिरकर 5999 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 32 रुपये या 0.53 फीसदी गिरकर 5999 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा 354.9 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 359.2 रुपये और नीचे में 351.6 रुपये पर पहुंचकर, 352 रुपये के पिछले बंद के सामने 6.5 रुपये या 1.85 फीसदी की तेजी के संग 358.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 7.1 रुपये या 2.02 फीसदी की बढ़त के साथ 358.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 997 रुपये पर खूलकर, 20 पैसे या 0.02 फीसदी की नरमी के साथ 991.9 रुपये प्रति किलो पर आ गया। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 51364.66 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 35587.05 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 8285.55 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 830.70 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 63.25 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 515.46 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 698.02 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1883.70 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 3.36 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 17628 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 116866 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 38286 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 563817 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 63023 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 13448 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 33262 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 96677 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 23663 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 17939 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 48300 पॉइंट पर खूलकर, 51199 के उच्च और 46400 के नीचले स्तर को छूकर, 2933 पॉइंट घटकर 46400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 22.4 रुपये की गिरावट के साथ 312 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.65 रुपये की बढ़त के साथ 41.1 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 6861 रुपये की गिरावट के साथ 7300 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 400000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 25618.5 रुपये की गिरावट के साथ 21201 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1390 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 43.41 रुपये की गिरावट के साथ 55.02 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 342.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 83 पैसे के सुधार के साथ 6.99 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5900 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 22 रुपये की बढ़त के साथ 274.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3.9 रुपये की गिरावट के साथ 33.1 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 2704.5 रुपये की बढ़त के साथ 4465.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 6766.5 रुपये की बढ़त के साथ 14000 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 17.7 रुपये की बढ़त के साथ 44.37 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 277.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 16 पैसे के सुधार के साथ 0.39 रुपये हुआ।